Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969."

MR. SPEAKER: The question is:

"That this House do further extend upto the last day of the current session, the time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill further to amend the Companies Act, 1956, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969."

The motion was adopted.

13.04 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

FAILURE OF GOVERNMENT TO LAY ON THE TABLE REPORT OF THE TARIFF COMMISSION

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में भी टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट्स का मामला मैंने उठाया । 16 तारीख को जो बहस हुई उस में आप ने मंत्रियों को फटकारा भी था और कहा था कि इस को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे । इस के बाद व्यापार मंत्री से और आप से मेरा पत्र-व्यवहार भी होता रहा । आप की तवज्जह मैं व्यापार मंत्री के इस पत्र की ओर दिलाना चाहता हूं । उन्होंने मुझको कहा कि सत्र शुरू होते ही मैं अपनी रिपोर्ट को रख रहा हूं और उन्होंने बाकी तीन रिपोर्ट्स के बारे में कहा था:

"So far as other Ministers are concerned in respect of which some three Reports are outstanding. I have written to my colleagues to take action on similar lines."

व्यापार मंत्री ने लिखने के बाद भी अभी तक इन मंत्रियों को सद्बुद्धि नहीं हुई है टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट को प्रकाशित करने की ।

व्यापार मंत्री के साथ मेरा जो पत्र-व्यवहार हुआ उस में से एक बात और निकली कि एक और रिपोर्ट जो पैट्रोलियम मंत्रालय के संबंध में है यह 1966 में टैरिफ कमीशन ने दी थी । वे अभी तक सो रहे थे । इतने पत्र-व्यवहार के बाद यह सत्य निकला और चूंकि चट्टोपाध्याय जरा भले आदमी मालूम पड़ते हैं इसलिए उन्होंने इस सत्य को कबूल किया वरना इस तथ्य का पता किसी को भी नहीं चलता ।

अध्यक्ष महोदय, और दो रिपोर्ट्स हैं । एक सिन्थेटिक रबर के बारे में है जिस का पैट्रोलियम मंत्रालय से संबंध है और एक उद्योग मंत्रालय से संबंधित रिपोर्ट है लिनोलियम वगैरह के बारे में—

"The fair prices of jute....

सिंथेटिक रबर वाली रिपोर्ट इन के पास सितम्बर 1971 में आई थी । लेकिन ऐसा लगता है कि अपने दो तिहाई बहुमत का इन लोगों को इतना गर्व हो गया है कि वे सोचते हैं कि संसद के अधिकारों के ऊपर वे आक्रमण कर सकते हैं । इसीलिए तकरीबन दो साल हो गए, यह रपट नहीं आई ।

इस के बारे में दो बात मैं कहना चाहता हूं । सिंथेटिक रबर की जो किलाचंद वाली कम्पनी है उस की टोटल मोनोपली है, और कोई कम्पनी नहीं है और आश्चर्य की बात है कि इस का सेल जो है कृत्रिम रबर का यह विगत साल एक प्रतिशत घटा है लेकिन इन की जो आमदनी है वह दस प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गई है । सेल घटने के बाद भी दस प्रतिशत आमदनी बढ़ती है । अब कृत्रिम रबर का एक हिस्सा टायर बनाने के लिए इस्तेमाल में आता है, औद्योगिक विकास मंत्रालय को टायर के बढ़ते हुए दामों के बारे में मैंने लिखा था और उन्होंने मुझको जो चिट्ठी भेजी है उस में कबूल किया है कि दाम बढ़

[श्री मधु लिमये]

रहे हैं और छोटे जो आपरेटर्स हैं उन को बड़ी तकलीफ हो रही है और उस के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं इस के बारे में जानकारी उन्होंने मुझको दी है । लेकिन टायर का दाम बढ़ने का एक बड़ा कारण यह है कि सिंथेटिक रबर के बारे में जो रिपोर्ट तकरीबन दो साल पहले प्रकाशित होनी थी वह प्रकाशित नहीं की गई । तो जितनी मुनाफाखोरी रबर बनाने वाली कम्पनी ने की है और टायर के दाम बढ़े हैं उस की जिम्मेदारी किस की है ? यह जो सिंथेटिक रबर कम्पनी है, एक तरह का कृत्रिम रबर जो वह बनाती है उस के बारे में मुझे जानकारी दी गई है कि उस का इस्तेमाल बाटा शू कम्पनी और दूसरी कोई प्राइवेट कम्पनी है साहू जैन की या किस की है मुझे पता नहीं है, वह करती है । अब इन का यह कहना है कि टैरिफ कमीशन ने जो सुझाव दिए हैं उस के अनुसार उस चीज के दाम घटाए जाएंगे तो बाटा और साहू जैन को 80 लाख का फायदा होगा । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट आने के बाद 1972 का बजट आया, 1973 का बजट आया । आप इस के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा कर यह आदेश दे सकते थे बाटा को और साहू जैन को उनके द्वारा बनाये गये जूतों का एक धेला दाम हम बढ़ाने नहीं देंगे । एक्साइज ड्यूटी का बोझ आप को ही सहना पड़ेगा । क्योंकि अगर ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएंगे और जूते का दाम बढ़ाया जायगा, सारा भार नागरिकों के ऊपर ही पड़ेगा तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है । तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा कर साहू जैन को और बाटा को जो कि ज्यादा पैदा करता है, इन दोनों को आप यह आदेश दे सकते थे । यह इन के न करने से 80 लाख की लूट हुई है किलाचंद के द्वारा और उस में से चुनाव के लिए आपको कितना मिला वह शायद आप को पता नहीं होगा, यह घर मंत्री साहब को पूरा पूछा जाय या जो चन्दा जमा करने वाले लोग हैं उन को पूछा जाय . . .

एक माननीय सदस्य : आप को कितना मिला ?

श्री मधु लिमये : मुझको तो एक धेला भी कभी नहीं मिलता है क्योंकि इन सवालों को मैं उठाता हूं और न मुझको उन के पैसे चाहिए । मैं तो उन का पैसा चाहता नहीं हूं . . . . . (**व्यवधान**) . . . . यह बेकार की बात करते हैं । मुझे इन लोगों के पैसे की जरूरत नहीं है । उस की तो आप लोगों को ही जरूरत है ।

अब दूसरा जो सवाल है वह उद्योग मंत्रालय के संबंध में है । मैं जानना चाहता हूं टैरिफ कमीशन ऐक्ट आप ने बनाया, टैरिफ कमीशन ऐक्ट के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि तीन महीने के अंदर रपट मिले और सरकार उस के ऊपर क्या कार्यवाही करती है उस को जानकारी दे, आप ही अपने कानूनों को तोड़ेंगे और संसद के अधिकारों को तोड़ेंगे तो यह नहीं चलने वाला है । उद्योग मंत्रालय ने अपनी रपट प्रकाशित नहीं की है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि न केवल यह सदन से माफी मांगें बल्कि जो मुल्जिम और दोषी लोग हैं उन के खिलाफ जांच करने का काम भी करें । यदि यह करने के लिए तैयार नहीं हैं तो पार्लियामेंट की किसी कमेटी को आप कहिए कि टैरिफ कमीशन के मामले में जो लगातार हर साल वायलेशन हुआ है और यह 66 का मामला तो 7 साल का मामला है उस के बारे में वह जांच करे और जो दोषी लोग हैं उन को सजा देने का काम करें ।

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRAMANIAM): I wish to submit to the House that there has been a failure on our part to place a copy of the report of the Tariff Commission on Fair prices of Jute-based and Felt-based Linoleum, within the period

stipuated in sub-section 2 of section 16 of the Tariff Commission Act, 1951. The report was received by the Government in June 1971. It had suggested a set of fair selling prices for various types of linoleum products. Two questions had to be examined in my Ministry. One was the legal question of the feasibility of issuing a normal price control order, either under the Industries Development Regulation Act or under the Essential Commodities Act. The second question was whether in the event of a formal price control not being possible, purchases by Government could be brought within a price control arrangement on a voluntary basis. The matter was being examined in consultation with various Ministries and came to my personal notice only when I called for the papers on receipt of the notice from the Hon'ble Member Shri Madhu Limaye.

I would like to submit without any qualification that there has been a lapse on our part in not taking the decisions on the recommendations of the report quickly and placing the Tariff Commission's report along with Government's decision within a ressonable period on the Table of the House. I would like to express my deepest regret to you, Sir, and to the House for this delay. I have already issued instructions for completing the further processing of the case with the top-most priority. I would also like to assure the House that the report with the Government's decision thereon will be placed before Parliament during the current session.

I have already asked for the explanation of the officers concerned for the inordinate delay in processing this case. I may be permitted to submit that no disrespect to the House or infringement of the rights of the Hon'ble Members was in the least intended. I would request that on the basis of this explanation and the assurance given by me the matter may kindly be not pursued at this stage.

MR. SPEAKER: This is an unqualified regret.

SHRI H. M. PATEL (Dhandhuka): How did it come about? How did the delay occur?

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad): I want the Minister to tell the House in specific and concrete terms as to what are the reasons and factors which have caused the delay. I do not want mere regret. He should come with an apology.

SHRI C. SUBRAMANIAM: This is the very thing I am enquiring into. When the inquiry is over, I will inform the House.

MR. SPEAKER: I very much appreciate that you have owned it and accepted it. I greatly appreciate the spirit with which you have given the reply.

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI D. K. BOROOAH): I am grateful to Mr. Madhu Limaye for bringing it to the notice of the House. In fact, it came to my notice somewhat earlier and I immediately took action in the sense that I got it examined, and I placed it before the Cabinet Committee and the Cabinet Committee has come to certain decision, on the basis of which orders are being issued. But as I have earlier pointed out, whatever was reduced from synthetic rubber companies' share gets into the coffers of Bata and one or two other industries because they are the main purchasers of this commodity and there is no point in robbing Peter to pay Paul. The Finance Minister is looking into this problem how to put excise duty on this and mop up this benefit which is a windfall for some of these monopoly houses.

SHRI MADHU LIMAYE: No burden on the consumers?

SHRI D. K. BOROOAH: No burden on the consumers. In any case, had the windfall gone to the monopolists they would have never passed it on to the consumers. That is a known fact. That note came to the Ministry on 3rd September, 1971 and under the law it has to be placed before the House within three months.

I quite see that there has been a very grave lapse on our part, and I sincerely apologise to this House for this.

I am today placing on the Table the report of the Tariff Commission the fair selling prices of synthetic rubber, along with a note which I have prepared on this, giving the details of the delay, the reasons why there has been delay and so on. But I can say that it will be sorted out certainly in this session.

There is another item which is a very small item, namely B.O.N. Acid, about which nobody seems to have known anything. It has been cleanly forgotten. It is a small item. It is about 900 tonnes or something of that sort. Nobody seems to have known anything about it. Shri Madhu Limaye brought it to my notice. It had become part of the archives as it were, and I have brought it out now. I am also deciding on this as soon as it is possible.

In the meanwhile, I have asked the Ministry to find out the person or persons who were responsible for this delay, and I think that we shall be able to take some measures in this behalf.

There was one thing on which certainly Shri Madhu Limaye's intervention was masterly but which he has absolutely ruined and tainted by referring to other things which are not material. So far as I am concerned, I did not need any money, for two reasons. One is that I came to the Rajya Sabha. So far as my election was concerned, I did not need any money for my elections, because I was elected uncontested. In a House of 114, there were 95 Congress Members, and so, I had no difficulty in being elected unopposed.

But Shri Madhu Lmaye fought a very highly contested election where he must have spent money. (*Interruptions*) Shri Madhu Limaye fought a very hotly contested election....

SHRI MADHU LIMAYE: I won an easy victory.

SHRI D. K. BOROOAH: He did, I know that.

SHRI DARBARA SINGH (Hoshiarpur): Easy victory does not mean that there is no need of money.

SHRI P. G. MAVALANKAR: I have not spent anything more than the legal limit. (*Interruptions*).

श्री मधु लिमये : जहां तक एलेक्शन एक्सपेन्सेज का सवाल है, मैं बांका के बारे में कहता हूं कि आप एक जांच समिति नियुक्त कीजिये । यह मेरी चुनौती है ।

श्री देवकान्त बरुआ : मैं बतलाता हूं । In this case, when you stand for Lok Sabha, there are expenses. When you stand for Rajya Sabha, the expenses are minimal. All I can say is that as between Shri Madhu Limaye and myself, Shri Madhu Limaye's needs are greater than mine.